

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 787/2017

सीता यादव

—अपीलार्थी

बनाम

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् जयपुर।
2. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बस्सी, जिला जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.05.2017

आदेश की दिनांक : 19.07.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रत्यर्थी संख्या-1 के आदेश दिनांक 15.04.1988 द्वारा अध्यापक के पद पर छः माह की गई और अपीलार्थी को पदस्थापन हेतु पंचायत समिति बस्सी आवंटित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या-1 ने विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के आदेश दिनांक 11.08.01989 एवं 11.08.1990 की अनुपालना में आदेश दिनांक 12.12.1996 (अनुलग्नक-1) द्वारा जिला स्थापना समिति की बैठक आयोजित कर विभिन्न पंचायत समितियों में कार्यरत अध्यापक की सेवा नियमित करने के आदेश दिए गये। उक्त आदेश की अनुपालना में प्रत्यर्थी संख्या-2 के आदेश दिनांक 13.08.1997 (अनुलग्नक-2) द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 15.04.1988 से नियमित की गई। इस संबंध में प्रत्यर्थी संख्या-2 ने एक आदेश दिनांक 27.01.1998 (अनुलग्नक-3) द्वारा दिनांक 15.04.1988 से अपीलार्थी की सेवा नियमित करने के लिए आदेश जारी किया गया। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की पदोन्नति होने व अन्य विसंगतियों के निराकरण करते हुए अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी जिन्हें अपनी सेवाएं 9, 18 एवं 27 वर्ष हो गए हो व उन्हें नियमानुसार कोई पदोन्नति नहीं मिली, उन्हें उक्तानुसार पदोन्नति के समान वेतन श्रृंखला व चयनित वेतनमान स्वीकृत किए जाने हेतु आदेश दिनांक 25.01.1992 जारी किया, जिसके पेटा संख्या 3 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया कि कर्मचारी को उक्त चयनित वेतन श्रृंखला हेतु सेवाकाल की गणना उसके प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जायेगी, जबकि अपीलार्थी की सेवाएं नियुक्ति दिनांक से ही स्थाई/नियमित कर दी गई। अपीलार्थी की 09 वर्ष की सेवा पूर्ण

होने पर आदेश दिनांक 25.06.1999 (अनुलग्नक-4) द्वारा प्रथम चयनित वेतनमान प्रथम नियुक्ति तिथि 15.04.1988 से गणना करते हुए स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया, जबकि अपीलार्थी 24 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका है। अपीलार्थी दिनांक 31.01.2013 को सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी ने कई बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किए परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता जरिये प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 05.12.2016 (अनुलग्नक-5) द्वारा विधिक नोटिस प्रस्तुत कर द्वितीय चयनित वेतनमान दिए जाने का निवेदन किया गया लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 15.04.1988 से सेवा काल की गणना कर उसे द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाकर वेतन अन्तर राशि का भुगतान किया जावे तथा भुगतान में देरी के फलस्वरूप देय वेतन अन्तर राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को दिनांक 15.04.1988 को पूर्णतया अस्थाई/तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र दिनांक 22.12. 1998 के द्वारा राज्य सरकार से यह मार्गदर्शन चाहा गया था कि पंचायत समितियों द्वारा शिक्षा विभाग में स्थानांतरित होकर आये कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण स्क्रीनिंग के बाद इनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से ही कर दिये जाने के फलस्वरूप क्या इन कर्मचारियों की सेवायें भूतलक्षी प्रभाव से नियमित मानी जा सकती है। इस संबंध में विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 06.02.1999 से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन संबंधी अधिसूचना दिनांक 17.03.1989 के अनुसार ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति स्क्रीनिंग के बाद आदेश जारी किये जाने की तिथि से ही नियमित मानी जावेगी। इस प्रकार अपीलार्थी की सेवाएँ आदेश प्रसारित किये जाने की दिनांक 12.12.1996 से ही राज्य द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार नियमित मानी गई है। साथ ही वित्त विभाग के आदेश दिनांक 29.06.2009 के द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गये है कि चयनित वेतनमान नियमित नियुक्ति तिथि के आधार पर ही देय होगा इससे पूर्व भी राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग के आदेश दिनांक 03.11.1998 के अनुसार तदर्थ नियुक्ति की अवधि को चयनित वेतनमान इत्यादि के लिये मान्य नहीं किया गया है। साथ ही राज्य सरकार के नियमानुसार अपीलार्थी नियमित नियुक्ति के अनुसार ही चयनित वेतनमान प्राप्त करने की अधिकारी है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अपीलार्थी दिनांक 12.12.1996 से चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी है, जिसके अनुसार अपीलार्थी की 18 वर्ष

की सेवा अवधि दिनांक 12.12.2014 को पूर्ण होती है परन्तु अपीलार्थी दिनांक 31.01.2013 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण अपीलार्थी वांछित परिलाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 04.03.2022 के द्वारा समान अनुतोष में प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार अपीलार्थी की अस्थाई नियुक्ति दिनांक 15.04.1988 को हुई थी जिसमें यह अंकित था कि उनकी अस्थाई नियुक्ति अध्यापक पद पर तदर्थ आधार पर 6 माह के लिए अस्थाई रूप से की गई थी। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी की जो नियुक्ति दिनांक 15.04.1988 को हुई थी, वह नियमित नियुक्ति नहीं थी, बल्कि ad-hoc के रूप में हुई थी। यह भी स्पष्ट है कि बाद में अपीलार्थी की सेवाएं आदेश दिनांक 12.12.1996 के द्वारा जिला स्थाई समिति के निर्णय के अनुसार नियमित की गई थी। यह निर्विवाद है कि राज्य सरकार के अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की गई थी और स्क्रीनिंग के पश्चात जिला स्थापना समिति के आदेश से अपीलार्थी की सेवाएं नियमित की गई थी।

माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 द्वारा निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है:—

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:—

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades

the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

अतः माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवा नियमित मानी जाएगी। यह भी माना है कि वरिष्ठता या अन्य लाभ के संबंध में नियमितिकरण की दो भिन्न तारिख नहीं हो सकती।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की जो सेवाएं 12.12.1996 को स्क्रीनिंग के बाद नियमित की गई, उसकी पूर्व की सेवाओं को अपीलार्थी वरिष्ठता व अन्य लाभ के लिए अपनी सेवा अवधि में नहीं जुड़वा सकता है। अतः अपीलार्थी को जो नियमितिकरण की दिनांक 12.12.1996 से नियमित मानते हुए उसी दिनांक से सेवा परिलाभ स्वीकृत किए गये हैं उसमें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य